

## बार-बार पश्चिम एशिया में अपने सैन्य ठिकानों पर “पिन-पाइन्ट” बमबारी से अमेरिका खीजा

अपने यूरोपीय “मित्रों” पर ट्रंप ने खीज निकाली और उन्हें चेतावनी दी या तो वे लोग इस युद्ध में सीधे (डॉयरेक्ट) जुड़े वरना. . . . .

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 मार्च। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बढ़ते ईरानी हमलों के सामने खुद को लगातार असहाय महसूस करते हुए, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय देशों से ईरान के खिलाफ अभियानों में सीधे शामिल होने का आग्रह किया।

ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों से कहा कि वे होमरुज से अपना तेल ख़ुद जाकर लें। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका उन्हें पहले की तरह मदद नहीं करेगा। इसके विकल्प के तौर पर, उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपनी तेल ज़रूरतें अमेरिका से पूरी करें, जहाँ पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

इटली ने ईरान में लड़ाकू अभियानों के लिए जा रहे अमेरिकी विमानों को अपने सैगोनेला एयरबेस पर उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह अनुमति देने से उस समय इनकार किया गया, जब कुछ अमेरिकी विमान अपने

ट्रंप ने कहा, यूरोपीय देश अपना “ऑयल” स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते लाने की व्यवस्था खुद करें, अमेरिका इस मामले में उनकी मदद के लिए आयोगा, जबकि यूरोपीय देशों ने भी खाड़ी युद्ध में अमेरिका की मदद नहीं की है या वे लोग अमेरिका से “ऑयल” खरीद सकते हैं। अमेरिका के पास बहुत “ऑयल” है।

ट्रंप की यूरोपीय देशों से खीज के कई कारण हैं। उदाहरण के लिए इटली ने खाड़ी युद्ध में बमबारी कर लौट रहे अमेरिकी लड़ाकू विमानों को इटली की भूमि पर “लैंड” करने की इजाज़त नहीं दी, हालांकि युद्ध से पहले से ही इटली व अमेरिका के बीच इस बारे में पुराना अनुबंध व समझौता है।

ट्रंप इस बात से भी परेशान हैं कि कोई न कोई ईरान की मदद कर रहा है, अमेरिकी सेना के ठिकानों व अन्य सैन्य गतिविधियों की जानकारी ईरान तक पहुँच रही है, जिससे इतनी “पिन-पाइन्ट” बमबारी हो रही है।

अमेरिका के युद्ध संबंधी मामलों के मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन की प्रैस बीफिंग में गुस्से भरे शब्दों में कहा, अमेरिका को पूरी जानकारी है, रूस व चीन की इस युद्ध में क्या भूमिका है।

घरेलू अड्डों से उड़ान भरकर ईरान क्षेत्र की ओर जा रहे थे। इटली ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार किया कि संसद से परामर्श के लिए पर्याप्त समय

नहीं था।

यह एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि पहले से मौजूद समझौते के तहत, अमेरिकी विमानों को परिचालन क्षेत्रों

की ओर जाते समय इटली में उतरने की अनुमति थी। लेकिन इस बार इनकार के लिए कुछ विशेष कारण बताए गए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिंडर पेस भाजपा में शामिल

नई दिल्ली, 31 मार्च। भारत के पूर्व टेनिस स्टार लिंडर पेस मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार, केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू,

केंद्रीय मंत्री, भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने बताया कि पेस 19 वीं सदी के बांग्ला कवि व लेखक माइकल मधुसूदन दत्त के वंशज हैं।

सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में लिंडर पेस ने भाजपा की सदस्यता ली। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा ने लिंडर पेस को पार्टी में शामिल कराकर तुणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने लिंडर पेस का स्वागत करते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सोनिया गांधी स्वस्थ, गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिली

नई दिल्ली, 31 मार्च। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को मंगलवार को सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें 24 मार्च को बुखार होने के बाद सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोनिया गांधी अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टरों के अनुसार वे एक सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दी गईं।

सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार

गत 24 मार्च की रात को बुखार के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सोनिया गांधी को 24 मार्च की रात 10:22 बजे बुखार के चलते सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉ. डीएस राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरुण बसु की देखरेख में उन्हें एक सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स से इलाज दिया गया और उन्होंने इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दी। अब वे ठीक हो चुकी हैं और आज सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, ताकि घर पर उनका आगे का इलाज और फॉलो-अप हो सके।

## ‘अमेरिका व्यर्थ ही ऐसे युद्ध में लिप्त हुआ है, जो वो कभी जीत ही नहीं सकता’

अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट जैफरी सैक्स के खाड़ी युद्ध के विचार बड़े चौंकाने वाले, पर सटीक हैं

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 मार्च। शीघ्र अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स का पश्चिम एशिया संघर्ष पर हस्तक्षेप अपनी भाषा के कारण नहीं, बल्कि अपने आरोपों की व्यापकता के कारण अधिक उल्लेखनीय है। यह भू-राजनीति, अमेरिकी शक्ति और स्वयं राज्य सत्ता के बदलते स्वरूप तक को कठघरे में खड़ा करता है।

वर्तमान संकट को “दुनिया भर के “लूजर्स” (पराजितों) का युद्ध” बताते हुए, सैक्स मूलतः यह तर्क दे रहे हैं कि इस उभरते टकराव में कोई रणनीतिक विजेता नहीं है, सिर्फ दीर्घकालिक नुकसान के अलग-अलग स्तर हैं। उनका यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय संघर्षों को शून्य-योग (जीरो-सम) प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने की पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। इसके बजाय, वे इसके कई परिणाम देखते हैं, जैसे आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का लगातार क्षरण आदि। उनके अनुसार, जो देश सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हैं,

जैफरी सैक्स यह भी कहते हैं कि सबसे बड़ी विवाद की बात है, जिस तरह से “टैक बिलिनियर” (टैकनोलॉजी उद्योगों के अरबपति) मालिक, सरकार के प्रशासन पर भावी हो रहे हैं।

जैफरी सैक्स ने हाल ही में प्र.मंत्री मोदी व राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हो रही टेलीफोनिक बातचीत में एलन मस्क के भागीदार होने की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा, इस अपवित्र दोस्ती में, “जवाबदेही” (एकाउन्टबिलिटी) और प्रजातंत्रिय वैधानिकता की बलि चढ़ती है।

जैसे भारत, वे भी तेल की ऊँची कीमतों, बाधित व्यापार मार्गों और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण नुकसान उठाएंगे।

सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों के लिए उनकी चेतावनी इसी व्यापक आकलन पर आधारित है। इन देशों ने पिछले दशक में खुद को स्थिरता, निवेश और तेल के बाद के आर्थिक परिवर्तन के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, और ऐसे में एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में प्रवेश करना

उनके लिए अत्यंत आत्म-विनाशकारी होगा। सैक्स द्वारा इस्तेमाल किया गया “तेज विनाश” शब्द तत्काल सैन्य हार की भविष्यवाणी से अधिक एक प्रणालीगत विघटन की चेतावनी है, जहाँ वितीय बाजार खत्म हो सकते हैं, बुनियादी ढाँचा निशाना बन सकता है और वर्षों में बनाए गए वैश्विक साझेदारी संबंध रतों-रात कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन सैक्स यही नहीं रकते, उन्होंने सबसे तीखी आलोचना का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पाँच साल के अंतराल के बाद पहला बिज़नेस डैलिगेशन चीन दौरे पर

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल 29 मार्च से 4 अप्रैल तक चीन के दौरे पर है

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

देश के उत्तरी हिमालयी पड़ोसी चीन के साथ संबंधों को सहज बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हुए, भारतीय वाणिज्य मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों चीन की यात्रा पर है, जहाँ वह चीन के अपने समकक्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहा है। पिछले पाँच वर्षों के विराम के बाद यह इस तरह की पहली यात्रा है।

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) का एक प्रतिनिधिमंडल 29 मार्च से 4 अप्रैल तक शंघाई और चीन के जियांग्सू प्रांत

भारत और चीन के संबंध पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य टकराव के बाद काफी बिगड़ गए थे। वर्ष 2024 में ब्रिक्स समिट व 2025 में एससीओ समिट के दौरान प्र.मंत्री मोदी व चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की वार्ता के बाद हालात सामान्य होने शुरू हुए थे।

शंघाई के भारतीय महावाणिज्य दूतावास के काउन्सिलेट जनरल प्रतीक माथुर ने प्रतिनिधिमंडल की चीन की प्रमुख कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ मीटिंग करवाई।

के दौरे पर है, जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल हैं।

2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य गतिरोध के बाद पाँच वर्षों से अधिक समय तक चले ठहराव के उपरांत,

पिछले वर्ष दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध सामान्य होने के बाद, यह चीन जाने वाला पहला भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 मार्च। तटीय राज्य ओडिशा में उडिया गौरव को बहाल करने के मुद्दे पर सत्ता में आई पार्टी के लिए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दिवंगत बीजू पटनायक के खिलाफ अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए, पार्टी की राज्य इकाई को असहज स्थिति में डाल दिया है। बीजू पटनायक एक राजनीतिक महानायक और उडिया गौरव के प्रतीक माने जाते हैं।

दुबे ने हाल ही में आरोप लगाया कि 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान, बीजू पटनायक ने अमेरिकी सरकार, सीआईए और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया था। यह बयान राज्यभर में व्यापक आक्रोश का कारण बना हुआ है, और उनकी पार्टी के भीतर और बाहर, दोनों जगह दुबे की

## बीजू का अपमान “उडिया गौरव” का मुद्दा बन रहा है ओडिशा में

बीजू पटनायक पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे की अपमानजनक टिप्पणी ने भाजपा को अटपटी स्थिति में डाला

निशिकांत दुबे ने 27 मार्च को लोकसभा के बाहर कहा था कि 1962 के युद्ध में बीजू पटनायक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू तथा अमेरिका व सीआईए के बीच कड़ी का काम किया था। दुबे के इस बयान पर भारी बवाल खड़ा हो गया।

बीजू पटनायक को ओडिशा में राजनैतिक महानायक व उडिया गौरव का प्रतीक माना जाता है। बीजू जन्मा दल ने इस बयान पर भारी नाराज़गी व्यक्त की तथा आमतौर पर शांत रहने वाले नवीन पटनायक ने इस पर भारी गुस्सा जताया, यही नहीं ओडिशा की भाजपा सरकार ने भी दुबे के बयान को उनका निजी विचार बताया और उनके बयान की कड़ी आलोचना की।

राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि दुबे की टिप्पणी ओडिशा में “अंजैया इफैक्ट” ला सकती है। ज्ञातव्य है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी. अंजैया का अपमान कर दिया था और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में एनटी रामाराव ने इस अपमान को “तेलगु प्राइड” का मुद्दा बनाकर भारी जीत प्राप्त की थी।

कड़ी आलोचना हो रही है। गत 27 मार्च को लोकसभा के बाहर दुबे ने कहा था कि नेहरू ने 1962 का युद्ध अमेरिका के पैसे और सीआईए के सहयोग से लड़ा

था। उन्होंने कहा, ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका सरकार, सीआईए और नेहरू के बीच की कड़ी थे।

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दुबे की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ईरान 1 अप्रैल से अमेरिकी कंपनियों पर निशाना लगायेगा

तेहरान, 31 मार्च। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को लेकर खुली चेतावनी दी है। ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवालयूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अगर ईरानी नेताओं पर हमले जारी रहे, तो वह पश्चिम

गुगल, माइक्रोसॉफ्ट, एपल, इंटेल, आईबीएम, टेस्ला, बोइंग, डेल, एचपी, ओरेकल का नाम भी सूची में।

एशिया में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा। इस बयान से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और वैश्विक स्तर पर चिंता गहरा गई है।

ईरान ने साफ कहा है कि 1 अप्रैल से तेहरान समय के अनुसार रात 8 बजे के बाद अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों पर हमले शुरू किए जा सकते हैं। भारत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 31 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा सहायक अधिवक्ता के पद पर नियुक्त कई वकीलों को बिना किसी कारण मनमाने तरीके से हटाये जाने के खिलाफ दायर 19 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें पूर्ववत पदों पर वापस लगाने तथा जेडीए को अधिवक्ताओं की नियुक्ति व हटाने के लिए गाइडलाइन बनाने के आदेश दिए हैं। इस गाइडलाइन में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सहायक अधिवक्ता और पैनल एडवोकेट की नियुक्ति में महिला, एससी-एसटी वर्ग की भागीदारी भी हो।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट

अपने कई आदेशों में दोहरा चुका है कि अधिवक्ता न्यायिक प्रणाली में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, उनके कारण ही न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहता है। हाईकोर्ट ने इसी टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि एक वकील को नौकर की भांति नहीं समझा जा सकता, उन्हें पद से हटाने अथवा लगाने के लिए कोई ठोस वजह व कारण होना चाहिए।

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने अपने आदेश में जेडीए को निर्देश दिए हैं कि अधिवक्ताओं की नियुक्ति व हटाने के लिए विस्तृत पॉलिसी व गाइडलाइन बनाएं।

इन 19 याचिकाओं में से अधिकतर वर्ष 2025 में दायर की गई हैं, जिनमें से याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2009 से 2014 के बीच नियुक्त किया

19 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा “एक वकील को नौकर की भांति नहीं समझा जा सकता, उन्हें पद से हटाने अथवा लगाने के लिए ठोस वजह व कारण होना चाहिए।”

वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने अदालत को बताया कि “वर्ष 2014 में जेडीए ने आदेश निकाला था कि अधिवक्ता को तब ही हटाया जा सकता है, जब जोनल कमिश्नर उनके काम से नाखुश हो, पर उनके मुवक्किल प्रताप सिंह के काम से जोनल कमिश्नर खुश थे, फिर भी उन्हें हटाया गया।”

वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर ने भी कहा कि, उनके मुवक्किल राम सिंह के पास वर्ष 2012 में जेडीए द्वारा जारी संतोषप्रद कार्य का अनुभव पत्र है, परंतु पिछली कांग्रेस सरकार में राम सिंह को तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आदेश पर हटाया गया था।”

गया था। इन याचिकाओं में कुछ याचिकाएं वर्ष 2021 में भी दायर की गई थीं, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा और कांग्रेस सरकार, दोनों ने जेडीए में नियुक्त सहायक अधिवक्ताओं को मनमाने ढंग से हटाया। यह सर्वविदित है कि जेडीए में लगे कई पैनल अधिवक्ताओं को भी कांग्रेस व भाजपा सरकार ने अपनी सरकार बदलने के साथ ही हटाया है। अधिवक्ताओं की नियुक्ति और हटाने के तरीके से स्पष्ट होता है कि राजनैतिक रसूख और सत्ताधारी पार्टी के जजदारी वकीलों को ही नियुक्तियां मिलती रही है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान मुख्य तौर पर 2 याचिकाओं को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया। इनमें पहली याचिका प्रताप सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें वर्ष 2009 में सहायक अधिवक्ता के तौर पर नियुक्ति दी गई थी। इनका कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया था कि उन्हें पैनल एडवोकेटस और जेडीए के अधिकारियों के बीच सेतु का काम करना था। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और उनके सहायक अधिवक्ता योगेश कल्ला पैरवी के लिए पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि सहायक अधिवक्ताओं को पद से हटाने की कोई तिथि तय नहीं की गई थी, लेकिन यह जरूर कहा गया था कि अगर उनके कार्य से जेडीए असंतुष्ट रहता है तो उन्हें बिना नोटिस हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जेडीए ने एक आदेश निकाला था कि अगर जोनल कमिश्नर (उपायुक्त) आपके कार्य से खुश नहीं है तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसके बावजूद 14 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## नालंदा : शीतला मंदिर में भगदड़, 9 की मौत

पटना, 31 मार्च। बिहार में नालंदा जिले के शीतला माता मंदिर में भगदड़ में 9 लोगों की अबतक मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। नालंदा के

नालंदा के पुलिस अधीक्षक ने बताया गम्भी और भीड़ के कारण हादसा हुआ। इसमें 9 की मौत हुई है तथा सात अन्य घायल हुए हैं। प्रमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए व घायलों को 50,000 रु. की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने बताया कि गर्मी और भीड़ की वजह से घटना हुई है। हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी ने छानबीन शुरू कर दी है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## विचार बिन्दु

पराधीनता समाज के समस्त मौलिक निमियों के विरुद्ध है। —मन्तेस्वयु

## जनसुनवाई बन रही लोकतंत्र में उलटबांसी जैसी व्यवस्था

भा रतीय लोकतंत्र का मूल आधार उसका संविधान है जिसके अनुसार सत्ता का वास्तविक स्रोत यहां के नागरिक होते हैं। संविधान के अनुसार जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है ताकि वे उनकी इच्छाओं, समस्याओं और आकांक्षाओं को शासन-व्यवस्था के जरिये उनके समाधान का प्रयास करें। किंतु वर्तमान समय में जिस प्रकार जन-सुनवाईयों की परंपरा विकसित हो गई है, वह कई बार लोकतंत्र की मूल भावना से उलट प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र में जनता मौलिक न रहकर याचक बन गई है और जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी सामंतों की भूमिका में आ गए हैं। यह स्थिति संविधान सम्वत लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रकार का शोषण है। परंपरागत सामंती व्यवस्था में राजा सर्वोच्च सत्ता होता था। तत्कालीन समाज में जनता के पास शासन में भागीदारी का कोई अधिकार नहीं था और न कोई स्वतंत्र न्याय व्यवस्था। राजा के बोल ही कानून होते थे। राजा ही न्याय करता था और वही उसकी पालना करवाता था। इसलिए प्रजा के लिए न्याय पाने का एकमात्र रास्ता राजा का रहम-ओ-करम होता था जिसके सामने उसे अपनी फ़रियाद पहुंचाना भी मुश्किल था। ऐसे राजाओं की दंतकथाएँ भी बनी जिसमें फ़रियादी सीधे बादशाह के सामने दरबार में जा सकता था या उसे कभी भी पुरकार सकता था। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र का सिद्धांत इससे बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहां एक ऐसा संविधान है जिसमें बराबरी के साथ जनता सर्वोच्च होती है। शासन उसके प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। शासन किसी की मर्जी से नहीं बल्कि संवैधानिक तथ्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार चलता है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को केवल शिकायत करने वाला नहीं बल्कि निर्णय प्रक्रिया का भागीदार माना जाता है। संविधान नागरिकों को अनेक अधिकार देता है और राज्य की संस्थाओं को यह जिम्मेदारी देता है कि वे इन अधिकारों की रक्षा करें। इसलिए लोकतंत्र में जनता को अपने अधिकारों के लिए किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं होती चाहिए। मगर क्योंकि भारतीय जन-मानस अब भी सामंती सोच व परंपराओं से अपना पिंड नहीं छुड़ा पाया है इसलिए संविधान की प्रतिष्ठा किताबों में रह गई है। लोकतांत्रिक विधि से चुने गए प्रतिनिधियों को सेवा का नहीं राजसी ताकत का अनुभव होता है। हम भारत के लोग जिन्होंने अपना संविधान अंगीकार किया उसके अनुरूप संवैधानिक सदनों में बैठने वाले विधि-निर्माता होते हैं मगर उन्होंने अपने को आम-जन का निर्यात मान लिया है।

वास्तविकता यह है कि आज कई स्थानों पर जन सुनवाई कार्यक्रमों का स्वरूप किसी दरबार जैसा दिखाई देने लगा है। नेता मंच पर बैठे होते हैं, अधिकारी उनके साथ उपस्थित रहते हैं और जनता नीचे खड़ी होकर अपनी समस्याएं सुनाती है। यह दृश्य अनायास ही सामंती व्यवस्था की याद दिलाता है। लोकतंत्र में जहां प्रतिनिधि को जनता का सेवक होना चाहिए, वहां वह मौलिक की तरह व्यवहार करता दिखाई देता है। दुर्भाग्य से यह आदत केवल जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी अब नियमित रूप से जन सुनवाई आयोजित करने लगे हैं। जिलाधीश, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या अन्य प्रशासनिक अधिकारी सप्ताह में एक दिन जनता की समस्याएं सुनते हैं। सतही तौर पर यह व्यवस्था सकारात्मक लग सकती है क्योंकि इससे लोगों को अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश चिंताने के लिए है। यह मान लिया गया है कि सरकारी तंत्र इतना जटिल और दूरस्थ हो गया है कि आम नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी विशेष सुनवाई के दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही यह है कि नागरिकों की समस्याएं नियमित प्रक्रिया के माध्यम से हल हों। यदि लोगों को अपनी शिकायतों के लिए विशेष जन सुनवाई का सहारा लेना पड़े रहा है, तो इसका अर्थ है कि सामान्य प्रशासनिक तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में जन सुनवाई समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसकी स्वीकारोक्ति बन जाती है। स्थिति तब और अधिक विचित्र हो जाती है जब पुलिस अधिकारी भी जन सुनवाई करने लगते हैं। पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों की जांच करना होता है। वह न्यायप्रणाली का हिस्सा होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो उसे सीधे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार है। लेकिन जब लोगों को न्याय पाने के लिए पुलिस अधीक्षक या अन्य बरिष्ठ अधिकारियों को जन सुनवाई का इंतजार करना पड़े, तो यह न्याय प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि सामान्य स्तर पर शिकायतों को किस तरह निपटा जा रहा है। ऐसा सिर्फ लापरवाही, या अक्षमता के कारण नहीं होता। अन्याय बड़े कारण होते हैं, जिसे सब जानते हैं। संविधान ने जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों को अधिकार इसलिए दिए हैं ताकि वे जनता के हित में निर्बाध काम कर सकें। लेकिन जब यह संबंध उलट जाता है, तब सेवक मौलिक बन जाता है और मौलिक याचक की भूमिका में आ जाता है। इस समस्या का

यह कहना उचित होगा कि जन सुनवाई का विचार पूरी तरह गलत नहीं है। यदि इसे जनता के साथ संवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए, तो यह उपयोगी हो सकता है। लेकिन जब यह व्यवस्था सामंती दरबार की तरह दिखाई देने लगे और जनता को याचक की भूमिका में धकेल दिया जाय, तब यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत हो जाती है।

एक कारण राजनीतिक संस्कृति में आया परिवर्तन है। आज राजनीति में जनसेवा की भावना के स्थान पर शक्ति और प्रतिष्ठा की आकांक्षा अधिक दिखाई देती है। कई नेता जन-सुनवाई को जनता से संवाद का माध्यम नहीं बल्कि अपनी लोकप्रियता दिखाने के मंच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मीडिया कवरेज, फोटो और वीडियो के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि नेता जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और तुरंत समाधान कर रहे हैं। लेकिन यह प्रक्रिया केवल प्रतीकात्मक होती है। इसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र भी इस संस्कृति को बढ़ावा देने लगा है। अधिकारी जन-सुनवाई के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि वे जनता के प्रति संवेदनशील हैं। लेकिन यदि प्रशासनिक व्यवस्था वास्तव में प्रभावी हो, तो अधिकांश समस्याएं कार्यालयों में ही रोजाना हल हो जानी चाहिए। लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था में जनता और शासन के बीच संबंध अधिक समानता पर आधारित होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का काम केवल शिकायतें सुनना नहीं बल्कि ऐसी नीतियां बनाना है जिससे समस्याएं उत्पन्न ही न हों। यदि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को बार-बार जन सुनवाई में जाना पड़े तो यह नीति-निर्माण की विफलता को ही दर्शाता है। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होती है कि सरकारी योजनाएं सही ढंग से लागू हों और नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलें। अब तो डिजिटल-तकनीक और ई-गवर्नेंस के माध्यम से शिकायतों का समाधान अधिक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, हेल्पलाइन और समयबद्ध सेवा कानून जैसे उपाय जनता को बार-बार अधिकारियों के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। पुलिस व्यवस्था में बड़े सुधार की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक थाने में शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और निष्पक्ष जांच हो, तो लोगों को उच्च अधिकारियों को जन सुनवाई में जाने की आवश्यकता क्यों पड़े? पुलिस और जनता के बीच विश्वास का संबंध बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि नागरिक स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। नागरिकों को यह समझना होगा कि वे केवल वोट देने वाले नहीं बल्कि शासन के वास्तविक मौलिक हैं। यदि प्रतिनिधि या अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन नहीं करते, तो जनता को लोकतांत्रिक माध्यमों से उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया को केवल जन सुनवाई के कार्यक्रमों की तस्वीरें दिखाने के बजाय यह सवाल उठाने चाहिए कि अखिर ऐसे स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि जनता को बार-बार अपनी समस्याएं लेकर नेताओं और अधिकारियों के सामने जाना पड़े रहा है। इसी प्रकार सामाजिक संगठनों को भी प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की मांग उठानी चाहिए। यह कहना उचित होगा कि जन सुनवाई का विचार पूरी तरह गलत नहीं है। यदि इसे जनता के साथ संवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए, तो यह उपयोगी हो सकता है। लेकिन जब यह व्यवस्था सामंती दरबार की तरह दिखाई देने लगे और जनता को याचक की भूमिका में धकेल दिया जाय, तब यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत हो जाती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता का व्यवहार कैसा है। यदि सत्ता स्वयं को जनता का सेवक मानती है, और नागरिकों को सम्मान के साथ अधिकार प्रदान करती है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन यदि सत्ता स्वयं को मौलिक समझने लगे और जनता को अपनी समस्याएं लेकर उसके सामने उपस्थित होना पड़े, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोकतंत्र की मूल भावना को पुनः याद करें। जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों को यह समझना होगा कि वे जनता के मौलिक नहीं बल्कि सेवक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को इतना प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए कि नागरिकों को न्याय और सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी दरबार की आवश्यकता न पड़े। जब तक यह परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम लोकतंत्र की मजबूती के बजाय उसकी विघटन को ही उत्साह करते रहेंगे। लोकतंत्र का वास्तविक भागीदार अधिकारी नहीं बल्कि नागरिक ही हैं। नही जाएंगे बल्कि शासन की दिशा तय करने में उसकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित होगी। तभी लोकतंत्र का यह शोषण समाप्त हो सकेगा और जनता वास्तव में अपने अधिकारों की स्वामी बन सकेगी।

—अतिथि संपादक,  
राजेश बोड़ा  
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

## ईरान-अमेरिका टकराव : शक्ति, विचार और जनता के बीच निर्णायक संघर्ष

दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव आज की वैश्विक राजनीति का एक ऐसा केंद्र बन चुका है, जहां सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि विचारधाराएं, पहचान और शासन की वैधता भी आमने-सामने खड़ी हैं



डॉ. नीरज रावत

ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव आज की वैश्विक राजनीति का एक ऐसा केंद्र बन चुका है, जहां केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि विचारधाराएं, पहचान और शासन की वैधता भी आमने सामने खड़ी हैं। यह संघर्ष सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह उस बड़े प्रश्न का हिस्सा है कि इस्लामी सदी की दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या दुनिया नियंत्रण और भय के ढांचे को स्वीकार करेगी, या स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर निर्णायक कदम बढ़ाएगी।

इस पूरे परिदृश्य में दुनिया की प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं हैं। एक बड़ा वर्ग इसे इस्लामी एकजुटता के चरम से देखता है। उसके लिए ईरान का पश्चिम से टकराव एक प्रकार का सभ्यतागत प्रतिरोध है। शिया और सुन्नी मतभेदों के बावजूद यह भावना कई समाजों में दिखती है कि ईरान पश्चिमी प्रभाव के सामने झुकने से इनकार कर रहा है। यह दृष्टिकोण भावनात्मक रूप से प्रभावशाली जरूर है, लेकिन यह ईरान के भीतर की वास्तविकताओं को पूरी तरह सामने नहीं लाता।

ईरान की असली कहानी उसकी सीमाओं के भीतर लिखी जा रही है। वहां सत्ता का केंद्र केवल निर्वाचित सरकार नहीं है, बल्कि इस्लामिक रिजोल्यूशनरी

गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी है, जिसने दशकों में एक समानांतर शक्ति संरचना खड़ी कर ली है। यह संगठन केवल सुरक्षा तंत्र नहीं रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और आंतरिक नियंत्रण तक इसका प्रभाव गहराई से फैला हुआ है। यही कारण है कि ईरान के भीतर असंतोष केवल आर्थिक कठिनाइयों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिक्रिया है जो नागरिकों को स्वतंत्रता को सीमित करती है।

ईरान की युवा पीढ़ी इस असंतोष का सबसे मुखर चेहरा बनकर उभरी है। शिक्षा, इंटरनेट और वैश्विक संपर्क ने उनके भीतर तुलना की क्षमता पैदा की है। वे जानते हैं कि दुनिया के अन्य हिस्सों में नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, और इसी तुलना ने उनके भीतर बेचैनी को जन्म दिया है। महसा अमिनी की मृत्यु के बाद जो आंदोलन खड़ा हुआ, वह केवल एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं था। वह वर्षों से जमा हो रहे गुस्से का विस्फोट था।

इन प्रदर्शनों की विशेषता यह थी कि उन्होंने भय की संस्कृति को खुली चुनौती दी। महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से हिजाब कानूनों का विरोध किया। छात्रों ने विश्वविद्यालयों से सड़कों तक अपनी आवाज बुलंद की। कई शहरों में लगातार विरोध देखने को मिला। यह संकेत है कि ईरान के भीतर एक बड़ा वर्ग अब केवल सुधार नहीं, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन चाहता है। यह असंतोष किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। इसमें महिलाएं, युवा, पेशेवर वर्ग और यहां तक कि परंपरिक समाज के कुछ हिस्से भी शामिल हो रहे हैं।

ईरान की प्रवासी समुदाय ने इस असंतोष को वैश्विक स्तर पर एक संगठित आवाज दी है। कनाडा, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले ईरानियों ने लगातार प्रदर्शन कर यह सुनिश्चित किया है कि दुनिया इस

मुद्दे को केवल एक भू-राजनीतिक संघर्ष के रूप में न देखे, बल्कि इसे मानवाधिकार और स्वतंत्रता के प्रश्न के रूप में भी समझे। यह दबाव धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माण को भी प्रभावित कर सकता है।

दूसरी ओर, क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इजराइल के लिए ईरान एक प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। इस संदर्भ में अब्राहम समझौते जैसे घटनाक्रम यह दिखाते हैं कि मध्य पूर्व की राजनीति अब पुराने ढांचों से बाहर निकल रही है। कई अरब देशों ने अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए नए गठजोड़ बनाए हैं। यह बदलाव संकेत देता है कि भावनात्मक मुद्दों की जगह व्यावहारिक सोच ने ले ली है।

अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर स्पष्ट एकमत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो आक्रामक नीति सामने आई, उसने यह दिखाया कि अमेरिका अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन करने से नहीं हिचकिचाता। कासिम सुलेमानी की हत्या इसी रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका में एक मजबूत धारणा यह भी है कि लंबे युद्ध देश के हित में नहीं हैं। यही कारण है कि उसकी नीति में आक्रामकता और संयम दोनों साथ साथ दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। वैश्विक स्तर पर चीन और रूस इस संघर्ष को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनके लिए ईरान एक ऐसा साझेदार है जो अमेरिकी प्रभाव को संतुलित कर सकता है। ईरान-सऊदी अरब समझौता 2023 में चीन की भूमिका इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कूटनीतिक केंद्र बदल सकते हैं। दुनिया धीरे-धीरे एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, यह आकांक्षा सार्वभौमिक है। अंततः यह संघर्ष हमें एक बुनियादी प्रश्न के सामने खड़ा करता है। क्या हम ऐसी दुनिया को स्वीकार करेंगे जहां सत्ता का स्रोत भय और नियंत्रण हो, या हम ऐसी व्यवस्था

की ओर बढ़ेंगे जहां नागरिकों की आवाज और अधिकार सर्वोपरि हों। किसी भी रूप में थियोक्रसी (धर्म तंत्र) अंततः व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है। यह समाज को स्थिरता के नाम पर उधरवा और नियंत्रण की ओर ले जाती है। आज आवश्यकता केवल युद्ध को रोकने की नहीं है। आवश्यकता एक स्पष्ट वैश्विक दृष्टिकोण की है, जिसमें मानव कल्याण सर्वोच्च हो। लोकतंत्र, अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार केवल आदर्श नहीं हैं, बल्कि स्थायी शांति और प्रगति की आधारशिला हैं। जहां नागरिकों को बोलने का अधिकार होता है, वहां व्यवस्था स्वयं को सुधारने की क्षमता भी रखती है।

ईरान अमेरिका टकराव केवल दो देशों का विवाद नहीं है। यह उस दिशा का संकेत है जिसमें पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। इस मोड़ पर लिया गया हर निर्णय आने वाले समय की संरचना तय करेगा। यदि दुनिया ने केवल शक्ति और रणनीति को प्राथमिकता दी, तो परिणाम अस्थिरता और संघर्ष ही होगा। लेकिन यदि मानवता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को केंद्र में रखा गया, तो यह संकेत एक नए संतुलन और बेहतर व्यवस्था की शुरुआत भी बन सकता है।

अंत में, यह याद रखना होगा कि किसी भी संघर्ष की वास्तविक कसौटी उसकी सैन्य जीत नहीं होती, बल्कि यह होती है कि उसने मानव जीवन की गरिमा को कितना सुरक्षित रखा। यदि इस पूरे विमर्श में आम लोगों की पीड़ा, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को केंद्र में नहीं रखा गया, तो कोई भी जीत अधुरी ही रहेगी। यही इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई है और यही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी।

—डॉ. नीरज रावत,  
(अंतरराष्ट्रीय विषयों के जानकार)

## नक्सलवाद का “लाल आतंक” खत्म : “मोदी 3.0” की सबसे बड़ी उपलब्धि

यह भारत के लोकतंत्र की सफलता, सुरक्षा बलों की वीरता आदि की संयुक्त विजय है



डॉ. योगेश शर्मा

राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। जरा सोचिए, कितना भीषण रहा होगा चीन के माओवाद का यह दर्शन, जो हिंसक सशस्त्र क्रांति को प्रस्तुत करता है और लोकतांत्रिक संस्कृति के ऊपर बंदूक संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता है। दूसरी तरफ भारत की स्वाभाविक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और आदर्शवादी संस्कृति है, जो कानून तथा संविधान और जेट के माध्यम से होने वाली शांतिपूर्ण क्रांति की पक्षधर है। परंतु दुर्भाग्यवश, माओवाद का यह खूनी दर्शन 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत-विरोधी कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के प्रभाव में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ और इसे “नक्सलवाद” नाम मिला। नक्सलवाद को उस समय चीन की कम्युनिस्ट क्रांति से वैचारिक प्रेरणा मिली, और चीनी मीडिया ने इसे सिंग थंडर ओवर इंडिया (भारत में बसंत का तुफान) तक कहा था। नक्सलवाद का हिंसक मार्ग न केवल राज्य की संरचना के लिए चुनौती बना, बल्कि समाज में अस्थिरता और भय का कारण भी बना।

1967 में प्रारंभ हुआ नक्सलवाद छह दशकों तक एक खूनी संघर्ष के रूप में भारत के लगभग 12 राज्यों में फैल गया। चार मजदुराघात, कानूनी सैन्य जैसे नेतृत्व से गुजरते हुए यह आंदोलन भारत में माओवादी, वामपंथी और चरमपंथी हिंसा का भयानक उदाहरण बन गया। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र तक इसका प्रभाव रेड कॉरिडोर के रूप में दिखाई देने लगा। रेड कॉरिडोर की अवधारणा या सामाजिक न्याय के आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, घात लगाकर किए गए हमले, मारे गए लोगों के मृत शरीरों के साथ अमानवीय व्यवहार और सशस्त्र क्रांति के वैध उद्देश्यों का प्रयास—नक्सलवाद एक संगठित सशस्त्र हिंसक विचारधारा का प्रतीक बन गया। आधुनिक रूप से एक गंभीर विघटनवादी यह है कि कुछ बुद्धिजीवी, लेखक व सिनेमा जगत से जुड़े लोग समय-समय पर नक्सलियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते नजर आए।

2014 के बाद मोदी सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक बहुआयामी रणनीति अपनाई—खुफिया ऑपरेशनों में तेजी, सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, नोटबंदी के माध्यम से माओवादी फंडिंग पर प्रहार, नक्सली नेटवर्क को ध्वस्त करना, नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराना एनआइए और इडी द्वारा संयुक्त कार्रवाई, ड्रोन, सेटेललाइट इमेजिंग, डिजिटल मैपिंग का उपयोग, स्पेशल फोर्स को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार ने 2017 में समाधान डॉक्यूमेंट (SAMADHAN

नक्सलवाद को भूमिहीन, आदिवासियों और वंचित वर्ग का मसीहा बनाने का एक ढोंग प्रस्तुत किया गया। जल, जमीन और जंगल की लड़ाई के नाम पर इसे वैध उद्देश्यों का प्रयास किया गया। इसने स्वयं को भगवान बिरसा मुंडा और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों से जोड़ने का वैचारिक दुस्साहस भी किया। नक्सलवाद ने जिस प्रकार से छह दशकों का खूनी सफर तय किया, वह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह आंदोलन कहीं से भी कृषक, भूमिहीन या सामाजिक न्याय के आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, घात लगाकर किए गए हमले, मारे गए लोगों के मृत शरीरों के साथ अमानवीय व्यवहार और सशस्त्र क्रांति के वैध उद्देश्यों का प्रयास—नक्सलवाद एक संगठित सशस्त्र हिंसक विचारधारा का प्रतीक बन गया। आधुनिक रूप से एक गंभीर विघटनवादी यह है कि कुछ बुद्धिजीवी, लेखक व सिनेमा जगत से जुड़े लोग समय-समय पर नक्सलियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते नजर आए।

2014 के बाद मोदी सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक बहुआयामी रणनीति अपनाई—खुफिया ऑपरेशनों में तेजी, सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, नोटबंदी के माध्यम से माओवादी फंडिंग पर प्रहार, नक्सली नेटवर्क को ध्वस्त करना, नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराना एनआइए और इडी द्वारा संयुक्त कार्रवाई, ड्रोन, सेटेललाइट इमेजिंग, डिजिटल मैपिंग का उपयोग, स्पेशल फोर्स को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार ने 2017 में समाधान डॉक्यूमेंट (SAMADHAN

—स्मार्ट लीडरशिप, एप्रिसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनएबल इंटील्लिजेंस, डेशबोर्ड-बेस्ड केपीआई, हॉर्सिंग टेकनोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्ससेस टू फाइनिंगिंग) को लागू किया, जिन्होंने नक्सलवाद विरोधी रणनीति को अधिक व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाया। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का प्रभावी क्रियान्वयन। रेड कॉरिडोर में 10,000 किमी से अधिक सड़क निर्माण 8,000 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित, शिक्षा, रोजगार, आवास योजनाएं, आधार, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, 250ई एकलव्य विद्यालय,रेलवे और कौशल विकास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन ने स्थानीय जनसंख्या का विश्वास अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं, और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्व के जागरूक नागरिक-सभी स्थायी बर्धाई के पात्र हैं। केंद्र सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के प्रयास और विकास आधारित नीति ने भारत को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर दिया है।—यह लोकतंत्र, विकास, न्याय और समावेशन की प्रक्रिया की निर्णायक विजय और नए भारत की एक मजबूत तस्वीर है।

निस्संदेह, यह भारत के लोकतंत्र की सफलता, सुरक्षा बलों की वीरता, सरकार और आम नागरिकों के विश्वास की संयुक्त विजय है। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए भारत की केंद्र सरकार, हमारे सुरक्षा बल और देश के जागरूक नागरिक-सभी स्थायी बर्धाई के पात्र हैं। केंद्र सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के प्रयास और विकास आधारित नीति ने भारत को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर दिया है।—यह लोकतंत्र, विकास, न्याय और समावेशन की प्रक्रिया की निर्णायक विजय और नए भारत की एक मजबूत तस्वीर है।

—डॉ. योगेश शर्मा,  
(लेखक संवैधानिक अध्येता और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं।)

### राशिफल

#### बुधवार 1 अप्रैल, 2026

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2083, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सायं 4:18 तक, वृद्धि योग दिन 2:51 तक, वणिज करण प्रातः 7:07 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह। आज रविवीरक सायं 4:18 तक है। सर्वाथ सिद्धि योग सायं 4:18 से सूर्योदय तक है। भद्रा प्रातः 7:07 से सायं 7:25 तक रहेगी। आज चान्द पूर्णिमा व्रत, मन्वादि है। श्रेष्ठ चौथाडिपा: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:26 तक, शुभ 10:58 से 12:31 तक, चर 3:35 से 5:07 तक, लाभ 5:07 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:40

**मेष** परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

**तुला** व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

**वृष** व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्ने लगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

**वृश्चिक** आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं।

**मिथुन** परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**धनु** व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य बन्ने लगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

**कर्क** व्यक्तिगत प्रयासों से महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्ने लगे। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी।

**मकर** नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बन्ने लगे। आज शुभ कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**सिंह** आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**कुंभ** चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। बनेत कार्य बिगड़ सकते हैं। अनावश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

**कन्या** आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए/दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संचालित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध कार्यों/परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

**मीन** परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।







# 12वीं के विज्ञान, कला और वरिष्ठ उपाध्याय के परिणामों में छात्राओं ने बाजी मारी

## उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का परिणाम 97.52 प्रतिशत रहा

अजमेर/उदयपुर, (निर्स)। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेण्डरी कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तथा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2026 का परिणाम मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी सभागार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से वचुंअली जुड़ते हुए परीक्षा परिणामों की घोषणा की। कक्षा 12 के सभी संकायों तथा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का समेकित परीक्षा परिणाम 96.45 प्रतिशत रहा। इसके साथ ही आजादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर रहा जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम मार्च माह में जारी हुए।

शिक्षा मंत्री दिलावर मंगलवार सुबह ट्रेन से उदयपुर पहुंचे थे। सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद 9.35 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार में पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित विभिन्न संघटनों के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दिलावर वीसी के माध्यम से अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के मुख्यालय से जुड़े। प्रातः दस बजे शिक्षा मंत्री दिलावर के निर्देशन में



शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी किए।

कम्प्यूटर का बटन दबाकर परीक्षा परिणाम जारी किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, सलुम्बर विधायक शांतादेवी सहित अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोर्ड प्रशासक एवं संचालक आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ तथा बोर्ड सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ भी बोर्ड कार्यालय से वचुंअली जुड़े।

शिक्षा मंत्री दिलावर ने बताया कि उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा में कुल 28068 परीक्षार्थी पंजीकृत (पश्चिम) के निर्देश पर सहायक पुलिस

विवान वर्ग की परीक्षा का परिणाम 97.52 प्रतिशत रहा। इसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 97.02 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.34 रहा। विज्ञान वर्ग में 178051 छात्रों में से 146644 छात्र और 107248 छात्राओं में से 98636 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुईं हैं। वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में 30798 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 30580 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। विज्ञान वर्ग का परिणाम 93.64 प्रतिशत रहा। इसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 94.04 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता

प्रतिशत 92.82 रहा। वाणिज्य वर्ग में 20666 छात्रों में से 13976 छात्र और 9914 छात्राओं में से 8096 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुईं हैं। इसी प्रकार कला वर्ग की परीक्षा में कुल 591023 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, इसमें से 583201 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। कला वर्ग का परिणाम 97.54 प्रतिशत रहा। इसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.68 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 98.29 रहा। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में कुल 4114 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं जिसमें से 4067 परीक्षार्थी परीक्षा में

प्रविष्ट हुए। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम 97.20 प्रतिशत रहा। छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.46 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 97.77 रहा। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 1781 छात्रों में से 832 छात्र और 2286 छात्राओं में से 1328 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुईं हैं।

मंत्री दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में इस बार से 1 अप्रैल से सत्रारंभ करने की योजना बनाई थी, जिसे तब से समयानुसार पूर्ण कर रहे हैं। इस बार से सत्र 1 अप्रैल से किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों हेतु कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि होगी। गत सत्र में कार्यदिवसों की संख्या 235 थी जो अब बढ़ कर 244 हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली बार से गणित विषय की री-चेकिंग व्यवस्था प्रारंभ की थी, इससे पूर्व केवल री-टोटलिंग की व्यवस्था थी। इस बार से दो अन्य विषयों विज्ञान व अंग्रेजी में भी री-चेकिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई है। दिलावर ने कहा कि आगामी सत्र से विद्यार्थियों को वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों का मानसिक तनाव कम होगा और सुधार का मौका मिलेगा। इसके अलावा हर बच्चे तक शिक्षा ले सकें और पढ़ाई सुनिश्चित किया गया है।

# सीकर में मिट्टी की सुरंग ढहने से तीन दोस्तों की मौत

## खेलने के लिए बनाई गई थी मिट्टी की सुरंग

सीकर, (निर्स)। सीकर में खेलने के लिए बनाई गई मिट्टी की सुरंग ढहने से तीन दोस्तों की मौत हो गई। वहीं, चौथे दोस्त को जान बच गई, जिसके चिल्लाने पर लोगों को घटना बारे में पता चला। हादसा नेछवा थाना इलाके में सोमवार को गनेडू गांव में हुआ।

पुलिस के मुताबिक होलाश मेघवाल (10) पुत्र नारायण मेघवाल, गौतम सैनी (14) पुत्र रतनलाल सैनी, दीपेश नायक (12) पुत्र भंवरलाल नायक और कृष्ण खेत में

मिट्टी के 3 से 4 फीट ऊंचे टीले के नीचे बनाई सुरंग में खेल रहे थे। कृष्ण सुरंग बाहर की ओर था। बाकी तीनों दोस्त अंदर चले गए। इस दौरान अचानक मिट्टी ढह गई। होलाश, गौतम और दीपक मिट्टी के नीचे दब गए। कृष्ण के भी पैर मिट्टी में दबे थे। फिर भी उसने मिट्टी में दबे अपने दोस्तों को निकालने की कोशिश की। बात नहीं बनी तो चिल्लाने लगा, ऐसे में गांव के लोग वहां पर आ गए।

सूचना पर नेछवा पुलिस भी मौके

पर पहुंची। मिट्टी हटाकर तीनों को निकाला गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। होलाश के पिता नानुराम को 1 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है। दीपेश के पिता ने भी करीब डेढ़ से 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था। दीपेश और होलाश सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। नेछवा पुलिस का कहना है कि खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। तीनों के शव का पोस्टमॉर्टम के बाद घरवालों को सौंप दिया।

# जोधपुर में अवैध रिफिलिंग पर कार्रवाई

जोधपुर, (कासं)। महामंदिर के इमरतिया बेरा क्षेत्र में अवैध रूप से व्यवसायिक और घरेलू गैस की टंकियों का भंडारण और रिफिलिंग करने की सूचना पर रसद विभाग के निरीक्षक ने दबिश देकर आरोपी के खिलाफ ईसी एक्ट में केस दर्ज कराया है।

महामंदिर पुलिस ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक (पी) राजकरण बारहट ने इमरतिया बेरा महामंदिर क्षेत्र में घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की अवैध रूप से भंडारण करने की सूचना पर दबिश देकर मौके से रिफिलिंग के उपकरण और घरेलू तथा व्यवसायिक सिलेण्डर जप्त किए हैं।

# सायबर ठगी की शिकायत दर्ज

जोधपुर, (कासं)। शहर के केरू क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ में गत साल दिसम्बर में 13.28 लाख का फ्रॉड हो गया। उसने ऑनलाइन शिकायत दी थी। बाद में पता लगा कि उसके द्वारा ऑनलाइन एक स्क्रीम में पैसा लगाया गया था। सायबर फ्रॉड के शिकार की ऑनलाइन शिकायत पर एटीएस जयपुर की तरफ से संबंधित थाना राजीव गांधी नगर में रिपोर्ट भेजी गई। इस पर पुलिस ने जोरो नंबर की एफआईआर पर अब जांच आरंभ की है। थानाधिकारी रविंद्रपाल सिंह ने बताया कि केरू निवासी झुमराम चौधरी के साथ तब साल दिसम्बर को यह फ्रॉड हुआ था। उसने किसी स्क्रीम के झंसे में आकर ऑनलाइन रकम को जमा करवाया था।

# स्मैक तस्करी का भंडाफोड़, घर से स्मैक और नकदी बरामद

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन एंटी वेनम' के तहत नेवाल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी चोट की है। पुलिस ने एक घर पर दबिश देकर 6.86 ग्राम अवैध स्मैक और 6 लाख 42 हजार रुपए बरामद किए हैं।

पुलिस अधिकारी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देश पर 15 से 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 मार्च

को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पुनियां और वृत्ताधिकारी शिवरतन गोदारा के सुपरविजन में नेवाल थानाधिकारी नरेश कंवर के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। टीम ने झालरा निवासी राधेश्याम उर्फ राजू मीणा के घर पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी संतोष देवी उर्फ कविता मौजूद थी। उसकी मौजूदगी में तलाशी लेने पर एक कमरे में डबल बेड के बोक्स से नीले रंग की प्लास्टिक थैली बरामद हुई। थैली की जांच में एक पारदर्शी पाउच में मटमैले रंग का पाउडर

मिला, जो जांच में स्मैक पाया गया। इसका वजन 6.86 ग्राम निकला। साथ ही उसी थैली से 6,42,100 रुपए नकद भी बरामद हुए, जिसे प्रारंभिक तौर पर स्मैक की बिक्री से जुड़ा माना जा रहा है। पूछताछ में आरोपी की पत्नी ने बताया कि यह सामान उसका पति लाता था और उसे इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने स्मैक और नकदी को जब्त कर आरोपी राधेश्याम उर्फ राजू मीणा के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

# अवैध शराब के साथ छह गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नेट पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से शराब रखने और बेचने वालों की धरपकड़ करते हुए आधा दर्जन लोगों को पकड़ा।

बोरानाड़ा थाने के एसएसआई हरसहाय ने बोरानाड़ा से नारनाडी सर्विस रोड पर अवैध रूप से शराब बेच रहे भीयाराम को गिरफ्तार कर बेचने को रहे 48 पन्ने देशी शराब के जप्त किया। लुणी थाने के एसएसआई ओमसिंह ने धुंघाड़ा में अवैध रूप से शराब बेच रहे सावलदान को गिरफ्तार कर बेचने को रखी 30 पन्ने देशी शराब के जप्त किए। वहीं कक्कड़ थाने के हैड कांस्टेबल मोहनलाल ने गंगाणी गांव में अवैध रूप से शराब बेच रहे मुकेश को गिरफ्तार कर बेचने को रखे 29 पन्ने देशी शराब के जप्त किए। वहीं मंडोर थाने के एसएसआई जगदीशचन्द्र ने 8 मील मंडोर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेच रहे अल्लाफ को गिरफ्तार किया। विवेक विहार थाने के हैड कांस्टेबल मुरारीलाल ने एक रेक्टर विवेक विहार क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेच रहे बलविन्दर सिंह को गिरफ्तार किया।

# फर्जी दुल्हन बनकर ठगने वाले गिरोह को यूपी से पकड़ा

## चौमूं पुलिस ने पति-पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

जयपुर। चौमूं पुलिस ने शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पति-पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा से पकड़े गए हैं और पिछले चार माह से फरार चल रहे थे। पुलिस उपयुक्त (पश्चिम) के निर्देश पर सहायक पुलिस आयुक्त उषा यादव और थानाधिकारी हरबंदर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

थानाधिकारी हरबंदर सिंह ने बताया कि परिवारी पुरेश जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने परिचितों के माध्यम से शादी का प्रस्ताव देकर विश्वास जीता। भरतपुर और मथुरा

आरोपियों से पूछताछ जारी, अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना जताई है

में लड़की दिखाकर जल्दबाजी में शादी तय की गई और अलग-अलग बहानों से करीब 5 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने पौडित से दुल्हन के कपड़े, जेवर और अन्य सामान भी दिलवाया। होटल में शादी की रस्म पूरी करने के बाद सामाजिक दबाव बनाकर अतिरिक्त रकम भी वसूली गई। बाद में महिला दुल्हन गहने पहनकर वांशरूम

जाने का बहाना बनाकर फरार हो गई। जांच में सामने आया कि दुल्हन और उसका साथी पहले से ही पति-पत्नी हैं और यह गिरोह पूर्व में भी इसी तरह की वारदातें कर चुका है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मथुरा में दबिश देकर आरोपी टीटू सिंह (28) निवासी पचावर महावन, राधा (35) पत्नी टीटू सिंह और देवेन्द्र सिंह (52) निवासी डींग, भरतपुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। कार्रवाई में उपनिरीक्षक अशोक कुमार, हैड कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल मूलचंद, राकेश और महिला कांस्टेबल सुमन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

# निवाई में बरसात के साथ ओले गिरे

निवाई, (निर्स)। मौसम का मिजाज मंगलवार को भी बदला-बदला सा रहा। सुबह से ही आकाश में बादल छाए रहे जिससे सूर्य व बादलों के बीच आंध मिचोली का खेल चलता रहा। दोपहर बाद अचानक तेज बारिश हुई। विगत दो दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में भारी परिवर्तन चल रहा है। मंगलवार शाम को भी बारिश हुई। शहर के कुछ क्षेत्र में बरसात के साथ चने के आकार के ओले गिरे।

इसी प्रकार गांव पलेई में भी बेर के आकार के ओले गिरे हैं। बारिश से खेतों में काटकर रखी हुई फसलें गीली हो गईं। इसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। मौसम के बदलाव व बारिश के होने से सामान्य तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवा के चलने से गर्मी के मौसम में भी ठंड महसूस हो रही है। दिन के तापमान के साथ ही रात के तापमान में भी गिरावट चल रही है। मंगलवार को सुबह से शाम तक आकाश में बादल छाए रहे। दोपहर

में हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दोपहर बाद अचानक तेज बारिश हुई। किसान दशरथसिंह पलेई, रामजीलाल करीरिया, तुलसीराम चौधरी, गिरांज खटाणा, सीताराम माहुर व नाथूलाल कसाना सहित अन्य किसानों ने बताया कि बेमौसम बरसात से सिंचाय नुकसान के कुछ नहीं हैं। कटी हुई फसलों के गीले हो जाने से दाना कमजोर होने की संभावना हो गई है। जिससे भाव भी कम मिलेंगे।

खेत पर बने मकान में लगी आग : रामगंजमंडी उपखंड क्षेत्र के पीपाखेड़ी गांव में खेत पर बने एक मकान में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग बिजली की स्प्रिंग (तार) में खराबी के कारण लगी बताई जा रही है। आग लगने से खेत में रखा चारा और पाइप जलकर पूरी तरह खाक हो गए। इस घटना में करीब 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया।

# स्मैक सहित दो जनों को पकड़ा, बाइक जब्त

छबड़ा, (निर्स)। पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 21.55 ग्राम स्मैक व मोटरसाइकिल को जब्त किया।

सीआई राजेश खटाना के अनुसार विशेष अभियान ऑपरेशन नशा विनाश के तहत की जा नाकाबंदी के तहत जाब्ता कइयावन कच्चा रास्ता छबड़ा कर्वाई मुख्य रोड खोपर गांव पहुंचा। यहां आने-जाने वाले वाहनों को चैक कर रहे थे कि एक बाइक छबड़ा की तरफ से आ रही थी, जिस पर दो व्यक्ति बैठे थे। जिन्हें रोकना चाहा लेकिन उक्त बाइक चालक ने पुलिस वाहन व जाबे को देखकर अपने बाइक को तेज गति से कइयावन कच्चे रास्ते की तरफ ले जाने लगा, जिस पर संदेह होने पर पीछा कर डिटैन किया तो चालक से नाम पता पूछा तो बाइक चालक ने घबराई हुई स्थिति में अपना नाम राकेश मीणा (26) पुत्र मूलचन्द निवासी वाई नम्बर दो छीपाबडईद व पीछे बैठे व्यक्ति ने

आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया

अपना नाम व पता भगवान सिंह मीणा पुत्र मूलचन्द निवासी कइया थाना हरनावदाशाहजी का होना बताया। जिससे कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया। डिटैनशुदा भगवानसिंह मीणा की तलाशी लेने पर जैब में अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिली। आरोपी के कब्जे से मिली 21.55 स्मैक व एक बाइक को जप्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। स्मैक के ऋय-विक्रय के बारे में पूछा तो बताया कि यह स्मैक सुरेन्द्र मीणा निवासी प्रेमपुरिया छीपाबडईद से खरीदना बताया तथा रामचरण प्रजापति निवासी खोपर को बेचान करने की बात कही। इस पर आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

# मोर पर श्वानों का हमला

निवाई, (निर्स)। मंगलवार की सुबह रास्ते में विचरण कर रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। मोर की चीख पुकार सुनकर भारीगर्थ सैनी, धर्मराज कर्जोटिया व सोहन माली ने कुत्तों से मोर को बचा लिया।

# कोटा : जेकेलॉन अस्पताल परिसर में वाहन

## पार्किंग शुल्क को लेकर विवाद

### मरीज के परिजन व स्टैण्ड कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया था

कोटा, (निर्स)। नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित जेकेलॉन अस्पताल परिसर में संचालित वाहन स्टैंड पर मरीज के परिजन व स्टैण्ड संचालक कर्मचारियों के बीच पचीं शुल्क काटने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, इसमें मरीज के साथ आए परिजनों और पार्किंग स्टाफ के बीच झगड़ा हो गया। पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुए इस झगड़े में हाथापाई तक नौबत आ गई। झगड़े के दौरान पत्थरबाजी का भी मामला सामने आ रहा है। पूरा घटनाक्रम

विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई, झगड़े में दोनों तरफ के लोगों को चोट आई है

सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल के उप अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी गई, सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार बूंदी जिले से एक कार में कुछ जने मरीज को लेकर अस्पताल आए थे और जब वह कार

को लेकर निकलने लगे तो वाहन स्टैण्ड पर कार्यरत कर्मचारी ने उनको पार्किंग शुल्क कटवाने के लिए कहा था, जिसको लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। झगड़े में दोनों तरफ के लोगों को चोट आई। जेकेलॉन अस्पताल उप अधीक्षक

डॉ. अमित जोशी ने बताया कि जेकेलॉन अस्पताल स्टैण्ड पर हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर गये। अस्पताल उप अधीक्षक ने बताया कि कुछ जने कार से आये थे और पार्किंग शुल्क को लेकर दोनों तरफ से झगड़ा हो गया, जिसमें मरीज के परिजनों को भी चोट आई। स्टैण्ड पर कार्यरत कर्मचारियों को भी चोट आई है। मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। उप अधीक्षक ने कहा कि पुलिस जांच के बाद हमारी कमेटी बनाई जाएगी, अगर पार्किंग

कर्मियों की गलती हुई तो कठोर कार्यवाही की जाएगी।

नयापुरा थाने के सब इंस्पेक्टर दीपेन्द्र शर्मा ने बताया कि जेकेलॉन अस्पताल में वाहन पार्किंग शुल्क को लेकर मरीज के परिजनों व स्टैण्ड पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया था। दोनों तरफ से लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की शिकायत दी है, दोनों तरफ से शिकायत लेकर मामला दर्ज किया गया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

# खाईवाली करते दो गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर के एयरपोर्ट बंगला स्थित खोखरियां, सांसियों की ढाणी में दस साल के मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। वह खेलते हुए पड़ौसी के घर के गेट पर पहुंचा और वहां लगे कूलर की चपेट में आने से करंट लग गया। घटना के समय बारिश भी हो रही थी। बच्चों की मां ने पड़ौसी परिवार को नामजद कर केस दर्ज कराया है।

बनाइ पुलिस ने बताया कि खोखरियां, सांसियों की ढाणी में रहने वाला दस वर्षीय रेहान पुत्र पवन सांसी सोमवार की सुबह खेलते हुए पड़ौसी के मकान तक आ गया, जहां पर एक कूलर लगा हुआ था। इस दौरान वह कूलर के नजदीक आ गया और उसे करंट लग गया। हादसे में उसकी मौत

हो गई। मृतक रेहान की मां सुमन ने अपने पड़ौसी सोनाराम आदि के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गेट पर कूलर लगाने से हादसे में उसके बच्चे को जान गई है। बनाइ पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद परिजन को सुपुर्द किया गया है। इसमें अंतिम जांच की जा रही है। वक्त घटना क्षेत्र में बारिश भी हो रही थी।

# खार्डवाली करते दो गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर के एयरपोर्ट बंगला स्थित खोखरियां, सांसियों की ढाणी में दस साल के मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। वह खेलते हुए पड़ौसी के घर के गेट पर पहुंचा और वहां लगे कूलर की चपेट में आने से करंट लग गया। घटना के समय बारिश भी हो रही थी। बच्चों की मां ने पड़ौसी परिवार को नामजद कर केस दर्ज कराया है।

बनाइ पुलिस ने बताया कि खोखरियां, सांसियों की ढाणी में रहने वाला दस वर्षीय रेहान पुत्र पवन सांसी सोमवार की सुबह खेलते हुए पड़ौसी के मकान तक आ गया, जहां पर एक कूलर लगा हुआ था। इस दौरान वह कूलर के नजदीक आ गया और उसे करंट लग गया। हादसे में उसकी मौत

हो गई। मृतक रेहान की मां सुमन ने अपने पड़ौसी सोनाराम आदि के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गेट पर कूलर लगाने से हादसे में उसके बच्चे को जान गई है। बनाइ पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद परिजन को सुपुर्द किया गया है। इसमें अंतिम जांच की जा रही है। वक्त घटना क्षेत्र में बारिश भी हो रही थी।



# अब राजस्थान के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली- भजनलाल

## मुख्यमंत्री ने सोमवार रात पोस्ट कर के इस उपलब्धि की औपचारिक घोषणा की

जयपुर, 31 मार्च। प्रदेश के 22 जिलों के बाद, अब दौसा एवं करौली जिले में भी कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली सुलभ होने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पोस्ट करके यह बड़ी घोषणा की।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है। इस क्रम में वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में यह कार्य चरणबद्ध रूप से वर्ष 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल प्रदेश के 22 जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अब जयपुर विद्युत वितरण निगम के दौसा एवं करौली जिले भी इससे जुड़ने जा रहे हैं।

फिलहाल जयपुर डिस्कॉम के 7 जिलों, धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीए एवं भरतपुर, के किसानों को सिंचाई के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली उपलब्ध हो रही है।

इसी तरह अजमेर डिस्कॉम के 12 जिलों- अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, बांसवाड़ा, झुझुनु, सीकर, चित्तौड़गढ़ एवं इंगूरपुर तथा जोधपुर डिस्कॉम के 3 जिलों, जालौर, सिरोंही



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

एवं पाली में भी कृषकों को दिन के दो ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

विगत समय में जयपुर डिस्कॉम ने दौसा एवं करौली जिलों में विद्युत तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। दौसा जिले में 33 केवी के 18 तथा करौली जिले में 33 केवी के 6 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही, दौसा में 33 केवी के 47 सब

स्टेशनों पर ट्रांसफार्मरों में 128.95 एमवीए की क्षमता वृद्धि की गई है। वहीं, करौली में 33 केवी के 15 सब स्टेशनों पर 49.45 एमवीए की क्षमता बढ़ाई गई है। दोनों जिलों में पीएम कुसुम योजना के कम्पैनेट-ए एवं कम्पैनेट-सी में 32 मेगावाट क्षमता के 17 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसका लाभ दौसा जिले में 52,460 तथा करौली जिले में 35,341 कृषि

## बार-बार पश्चिम एशिया में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रबियो ने कहा है, अब "नाटो की पुनर्समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि कुछ सदस्य देशों ने स्पष्ट रूप से अपने एयरबेस का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।"

इस बीच, ईरान ने सक्रमी अरब में अमेरिकी सेना के एक कॉन्क्रेस स्थल के पास स्थित एक लक्ष्य पर बमबारी की, जहाँ लगभग 200 वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारी पश्चिम एशिया में अपने अभियानों पर चर्चा कर रहे थे। बड़ी संख्या में अधिकारियों के हताहत होने की आशंका है, हालांकि अमेरिकी सेना की ओर से अभी तक इस हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

ईरान ने दिन के दौरान, कुवैत के एक बड़े तेल टैंकर को भी निशाना बनाया, जिससे आग लग गई और

वैश्विक बाजार के लिए तेल परिवहन बाधित हो गया। इन दोनों हमलों को एक बार फिर अत्यंत सटीक माना जा रहा है, जिससे बाहरी शक्तों से खुफिया जानकारी मिलने की आशंका भी जताई जा रही है।

होर्मुज जलमंदरूमध्य (स्ट्रेट) के लगातार बंद रहने और तेल एवं ऊर्जा सुविधाओं पर बढ़ते हमलों ने तेल की वैश्विक कीमतों को और बढ़ा दिया है। नवीनतम तेल बाजार रिपोर्ट के अनुसार, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है।

अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़कर 4 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका है और ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा रही हैं।

अमेरिकन रक्षा मुख्यालय पेंटागन में हुई एक ब्रीफिंग के दौरान, युद्ध सचिव

पीट हेगसेथ ने कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका को पूरी जानकारी है कि रूस और चीन कहाँ, क्या कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका इन चुनौतियों का सीधे सामना कर रहा है और अपनी रणनीति के अनुसार उनसे निपट रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका रूस और चीन की गतिविधियों पर करीबी नजर रखे हुए है। ट्रंप ने इन मुद्दों से निपटने में फ्रांस की गैर-सहयोगी भूमिका की भी आलोचना की।

अब अमेरिकी सैन्य नेतृत्व यह स्वीकार करने लगा है कि ईरान को कहीं और से सूचना मिल रही है, जिससे उसके हमले अधिक सटीक और प्रभावी हो रहे हैं। अमेरिका ईरान से बातचीत करने और समझौता करने की अपील कर रहा है, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

## सूरत के एक मकान में विस्फोट, पांच की मौत

सूरत, 31 मार्च। गुजरात के सूरत के लिंबायत क्षेत्र में मीठी खाड़ी के पास स्थित एक मकान में केमिकल में विस्फोट होने से भीषण आग लगने से 5

## मकान में साड़ियों का काम होता था व ज्वलनशील केमिकल रखा था, जिसमें ब्लास्ट से आग लगी।

लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल हो रहा है। पुलिस के अनुसार मकान में विस्फोट होने से भीषण आग लगने से 5

## बीजू का अपमान "उडिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य के विधि मंत्री पुष्पेराज हरिचंदन ने कहा कि पार्टी सांसद द्वारा व्यक्त विचार "पूरी तरह उनके व्यक्तिगत विचार" हैं और सरकार के रुख को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा, "ऐसी टिप्पणियाँ बहुत ही अनुचित हैं और किसी भी परिस्थिति में अपेक्षित नहीं हैं। इनसे न केवल मुख्यमंत्री मांझी, बल्कि हम सभी को गहरी पीड़ा हुई है।"

इस मामले में राज्य भाजपा की रक्षात्मक स्थिति समझ में आती है, क्योंकि लोगों के मन में बीजू पटनायक के प्रति गहरा सम्मान है। बीजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो आमजोर पर संयमित भाषा के लिए जाने जाते हैं, ने असामान्य रूप से कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक स्वतंत्रता सेनानी और सम्मानित नेता के खिलाफ ऐसे "बेतुके और पूरी तरह झूठे" बयान देने वाले दुबे को

मानसिक चिकित्सक से परामर्श लेने की जरूरत है।

भाजपा के भीतर भी प्रतिक्रियाएँ कम नहीं रही। पार्टी नेता और हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित दिलीप रे ने 'एक्स' पर लिखा: "बीजू बड़ा का जीवन साहस, त्याग, दूरदृष्टि और अडिग देशभक्ति का प्रमाण था। वे केवल ओडिशा के एक महान नेता ही नहीं थे, बल्कि उन दुर्लभ राष्ट्रनिर्माताओं में से एक थे, जिनके जीवन और कार्य ने भारत के राजनीतिक और रणनीतिक इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उनके इस असाधारण योगदान को हल्की और सनसनीखेज राजनीतिक टिप्पणियों तक ले आना न केवल अनुचित है, बल्कि अत्यधिक असम्मानजनक भी है।"

बीजद ने सोमवार को राज्यसभा में वाँकआउट किया। एक दिन पहले,

## आज से टोल पर नकद भुगतान बंद केवल डिजिटल पेमेंट होगा

नई दिल्ली, 31 मार्च। देशभर में सड़क इस्तेमाल करने वाले लोग एक अप्रैल से टोल चार्ज नकद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपनाने जा रहा है। हाईवे यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़े कदम के तौर पर एनएचएआइ देशभर के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगा देगा।

एक अप्रैल से यात्रियों को टोल चार्ज सिर्फ फास्टेग या यूपीआई जैसे

## हाईवे यात्रा की आधुनिक बनाने के लिए एनएचएआइ ने यह नया पारदर्शी कदम उठाया

डिजिटल तरीकों से ही देना होगा। इस कदम का मकसद नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन को अधिक कुशल बनाना और ज्यादा पारदर्शिता लाना है।

अधिकारियों का मानना है कि पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम से गाड़ियां टोल प्लाजा से अधिक तेजी से निकल पाएंगी, जिससे लंबी लाइनें नहीं लगेगी और यात्रा का समय बचेगा। टोल बुक पर तेजी से प्रोसेसिंग होने से ईंधन की खपत कम होने और प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है।

इस बदलाव से कुछ यात्रियों को परेशानी हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार नहीं हैं।

# जयपुर में गैस की कालाबाजारी पर एक्शन, 118 सिलेंडर व उपकरण जब्त

## जिला रसद अधिकारी के तीन विशेष दलों ने शहर में सघन निरीक्षण व कार्यवाही की

जयपुर, 31 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार तथा राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की अनुपालना में, जयपुर शहर में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अवैध रिफिलिंग, भण्डारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण द्वारा 03 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन कर शहर में सघन निरीक्षण एवं कार्रवाही की गई। इन दलों में प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया।

कार्रवाहियों के दौरान, कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 2 उपकरण, 3 रिफिलिंग मोटर, 1 रेगुलेटर एवं 1 पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। अवैध गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई हो रही है।

## खो नागोरियान में नारायण सिटी, जेएनयू अस्पताल के पास, आगरा रोड, गौरव जनरल भंडार व बिंदायका में घरेलू व व्यवसायिक गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर आदि उपकरण पकड़े गये।

उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जयपुर शहर में कार्यवाही हेतु तीन विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया। दल "ए" में कविता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी व सुनिता चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक विशेष प्रवर्तन दल "बी" में पूजा शर्मा प्रवर्तन अधिकारी व विजयलक्ष्मी शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक एवं विशेष प्रवर्तन दल "सी" में निर्मला चौधरी प्रवर्तन अधिकारी व प्रिया गंगवानी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कार्य की गई।

पुलिस थाना खो-नागोरियान क्षेत्र में नारायण सिटी, जेएनयू हॉस्पिटल के पास संयुक्त कार्रवाई के दौरान, अवैध रिफिलिंग की पुष्टि होने पर 74 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 3 रिफिलिंग मोटर तथा 1 पिकअप वाहन जब्त किया गया। इसी प्रकार, आगरा रोड स्थित गौरव बर्तन भंडार एवं जग्गा की ढाणी में दबिश के दौरान 22 गैस सिलेंडर एवं एक उपकरण जब्त किए गए। भांकरोटा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 8 गैस सिलेंडर, 1

कांटा एवं एक उपकरण जब्त किया गया, वहीं बिंदायका क्षेत्र में की गई कार्रवाई में 14 गैस सिलेंडर, 1 कांटा तथा 1 रेगुलेटर रबर पाइप सहित जब्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा संचालित 'ऑपरेशन प्रवर्तन - सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर' अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गैस रिफिलिंग, भण्डारण अथवा कालाबाजारी से संबंधित सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय रहते कठोर कार्रवाई कर आमजन की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

## ईरान 1 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के समय के अनुसार यह रात 10:30 बजे का समय होगा। ईरान ने कहा है कि हर हमले के बदले इन कंपनियों की यूनिट्स को तबाह किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को तुरंत अपने कार्यस्थलों से हटाने की चेतावनी भी दी गई है। ईरान ने 15 बड़ी अमेरिकी कंपनियों की सूची भी दी है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटरनेट, आईबीएम, टेस्ला और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा डेल, एचपी, सिस्को, ओरेकल और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। इससे साफ है कि ईरान अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहना चाहता।

## छत्तीसगढ़ में 25 इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया

बीजापुर, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलवाद के खामे की तय समय सीमा के अंतिम दिन, आज मंगलवार को बस्तर आईजी सुन्दरराज

## इनके पास से 93 घातक हथियार, 7.2 किलो सोना, व 2.90 करोड़ रु. नकद बरामद हुए।

पी., सीआरपीएफ के डीआईजी बी.एस. नेगी, बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव सहित, कई वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 25 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर 1.47 करोड़ का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने एलएमपी, एके-47, एसएलआर, इन्सास सहित, कुल 93 घातक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। पहली बार नक्सलियों के पास से 2.90 करोड़ रुपये नकद और लगभग 7.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत करीब 11.16 करोड़ रुपये आंकी गई है। इनके पास मिले हथियारों में 4 एके-47 और 5 एसएलआर राइफलें जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल हैं।

## ईरान के इस्फहान शहर पर अमेरिका ने भारी हमला किया

तेहरान/कुवैत सिटी/ बेरूत/ इजरायल, 31 मार्च। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के ऐतिहासिक शहर इस्फहान पर जबरदस्त हमला किया है। इस शहर की आबादी लगभग 23 लाख है। यहां बंदर मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद है। जोरदार धमाकों और आग की लपटों से आज सुबह तक आसमान में दहशत रोशन रही। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना पर हमलों का दावा किया है।

अल जजिरा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी ने इस्फहान में हमले के कई वीडियो तैयार किए हैं। इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा और सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह ईरान का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहां कपड़ा और इस्पात की मिलें हैं। यहां ईरान का

## 'अमेरिका व्यर्थ ही ऐसे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निशाना वांछित नहीं को बनाया है। उनका यह दावा, कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे युद्ध का समर्थन कर रहा है, "जिसे वह जीत नहीं सकता", अमेरिकी विदेश नीति की रणनीतिक सुसंगतता पर उनके गहरे संदेह को दर्शाता है। वे ईराक से लेकर अफगानिस्तान तक, एक पैटर्न देखते हैं, अत्यधिक विस्तार (ओवरसी) का, जहाँ विशाल संसाधन खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्थायी राजनीतिक परिणाम नहीं मिलता। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया में भी यही तर्क लागू हो रहा है: बिना विश्वसनीय अंतिम रणनीति के लगातार बढ़ता हुआ युद्ध।

उनकी टिप्पणियों का अधिक विवादास्पद, और राजनीतिक रूप से विस्फोटक हिस्सा उस कथित घटना से जुड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच एक उच्चस्तरीय कूटनीतिक बातचीत में एलन मस्क की मौजूदगी का दावा किया गया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रायता ने इसे आधिकारिक तौर पर खारिज किया है, पर सैक्स इस

प्रकरण, चाहे वास्तविक हो या अनुमानित, का उपयोग अमेरिका में संवैधानिक व्यवस्था के पतन के बड़े मुद्दे को रेखांकित करने के लिए करते हैं। यहाँ उनकी आलोचना विदेश नीति से हटकर राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ जाती है। सैक्स का तर्क है कि राज्य संचालन के मामलों में तकनीकी अरबपतियों का बढ़ता प्रभाव सार्वजनिक सत्ता और निजी शक्ति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है। जब अपार आर्थिक ताकत रखने वाले, निर्वाचित न हुए व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कूटनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल दिखाई देते हैं, तो यह जवाबदेही और लोकतांत्रिक वैधता के मूलभूत प्रश्न उठाता है। उनका कथन कि, "सरकार को खरीद लिया गया है" जानबूझकर बोला गया भड़काऊ कथन है, साथ ही यह एक व्यापक बहस को दर्शाता है कि केन्द्रित संपत्ति अब नीतिगत परिणामों को इस तरह प्रभावित कर रही है, जो संस्थागत नियंत्रण और संतुलन को दरकिनार कर देता है।

समग्र रूप से, सैक्स की टिप्पणियाँ एक ऐसी विव्यवृष्टि को दर्शाती हैं, जिसमें आज के संघर्ष अलग-थलग घटनाएँ नहीं, बल्कि गहरे संरचनात्मक संकटों के लक्षण हैं, शासन, वैश्विक व्यवस्था और आर्थिक असमानता के संकट। इस दृष्टिकोण में, पश्चिम एशिया का संघर्ष क्षेत्रीय या वैचारिक विवादों से अधिक तेजी से बदलती दुनिया को संभालने में बड़ी शक्तियों की विफलता को उजागर करता है।

भारत के पर्यवेक्षकों के लिए, सैक्स की टिप्पणियाँ दोहरे अर्थ रखती हैं। एक ओर, वे आस में जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूरस्थ संघर्षों में उलझने के जोखिम को रेखांकित करती हैं। दूसरी ओर, वे शक्ति के बदलते स्वरूप को उजागर करती हैं तो जहाँ राज्य, बाजार और तकनीकी अभिजात वर्ग तेजी से अप्रत्याशित तरीकों से एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं।

चाहे कोई उनके निष्कर्षों से सहमत हो या नहीं, लेकिन सैक्स एक असहज प्रश्न को सामने रख रहे हैं: ऐसी दुनिया में, जहाँ युद्धों के स्पष्ट विजेता नहीं होते और शासन स्वयं विवादित प्रतीत होता है कि आधिकार सत्ता किसके हाथ में है?

## नालंदा : शीतला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसपी भारत सोनी के अनुसार, अत्यधिक गर्मी और भारी भीड़ इस हादसे की मुख्य वजह रही। उन्होंने बताया कि ठंडे पानी में स्नान के बाद जब महिलाएँ मंदिर परिसर में प्रवेश कर रही थीं, तभी दम घुटने और पानी की कमी के कारण कई महिलाएँ बेहोश होकर गिरने लगीं। इससे अफरा-तफरी मच गई और भीड़ बँकावू हो गई, जिसके चलते यह दुखद घटना घटी।

इस बीच केंद्र और राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग से 04-04 लाख रुपये एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से (सीएमडीआरएफ) 02-02 लाख रुपये (कुल 06 लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है।

## पूर्व टेनिस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी भाजपा के मंच से देश की सेवा करेंगे। रिज्जु ने कहा कि देशभर में लिंएंडर पेस का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टेनिस स्टार के भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि लिंएंडर पेस 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्त के प्रत्यक्ष वंशज हैं।

## वकीलों को हटाना जेडीए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नवंबर 2025 को जेडीए ने प्रताप सिंह को बिना कारण बताए हटा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने अदालत में 11 नवंबर 2025 को जौनल कमिश्नर द्वारा जारी रिपोर्ट पेश की, जिसमें याचिकाकर्ता समेत कुछ अन्य वकीलों के कार्य को संतुष्टिपूर्ण बताया था।

अदालत ने दूसरी याचिका, जिसे अपने फैसले में उद्धृत किया, वह राम सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्हें वर्ष 2021 में, यानी पिछली गहलगत सरकार के कार्यकाल में जेडीए से हटाया गया था। रामसिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता साहिल शर्मा पेरवी के लिए उपास्थित हुए थे।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता सिलेंडर के पास वर्ष 2012 में जेडीए द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र हैं, जिसमें उनके कार्य को संतुष्टिपूर्ण बताया गया था। आर.एन.माथुर ने अदालत को बताया कि, उनके मुवाकिल राम सिंह को भी जेडीए प्रशासन ने हटाने का कोई कारण नहीं बताया, परंतु उन्हें तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आदेश पर हटाया गया था। राम सिंह को हटाने के तरीके से स्पष्ट होता है कि यह फैसला उन वकीलों को खुश करने के लिए था, जो तत्कालीन सरकार के करीबी थे और मंत्री को जान-पहचान के थे।

जेडीए की ओर से इस मामले में कहा गया कि सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी, यह जेडीए के कार्मिक नहीं थे। ऐसे में इन अधिवक्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है कि वे अपनी सेवाएँ जारी रखने का अधिकार प्राप्त कर सकें। इस पर अदालत ने कहा कि

जिसमें उनके कार्य को संतुष्टिपूर्ण बताया गया था। आर.एन.माथुर ने अदालत को बताया कि, उनके मुवाकिल राम सिंह को भी जेडीए प्रशासन ने हटाने का कोई कारण नहीं बताया, परंतु उन्हें तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आदेश पर हटाया गया था। राम सिंह को हटाने के तरीके से स्पष्ट होता है कि यह फैसला उन वकीलों को खुश करने के लिए था, जो तत्कालीन सरकार के करीबी थे और मंत्री को जान-पहचान के थे।

जेडीए की ओर से इस मामले में कहा गया कि सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी, यह जेडीए के कार्मिक नहीं थे। ऐसे में इन अधिवक्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है कि वे अपनी सेवाएँ जारी रखने का अधिकार प्राप्त कर सकें। इस पर अदालत ने कहा कि

अधिवक्ता न्यायिक प्रणाली में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, एक वकील को नौकर की भाँति नहीं समझा जा सकता, उन्हें पद से हटाने अथवा लगाने के लिए एक ठोस वजह व कारण होना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जेडीए ने इन अधिवक्ताओं को हटाने समय ऐसा कोई कारण या वजह नहीं बताई, जिससे उनकी कार्यशीली पर अस्तंभ जाहिर हो। इस मामले में अब यह देखा है कि अधिवक्ताओं को हटाने का कोई कारण था या जेडीए अधिकारियों ने अपनी मनमानी की थी। अदालत ने आगे कहा कि जेडीए की खुद को गाइडलाइन कहती कि आर.एन.माथुर को जेडीए अधिवक्ता से अस्तंभ दे तो उसे हटा सकता है, परंतु जेडीए की ओर से इस संबंध में कोई दस्तावेज अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

## 'केरल में हर साल दो गैस सिलेंडर मुफ्त देगी भाजपा'

तिरुवनंतपुरम, 31 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र मंगलवार को जारी कर दिया। "यही बदलाव है, यही विकसित केरल है" थीम पर आधारित इस घोषणापत्र में राज्य के समग्र विकास का रोडमैप पेश किया गया है, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है।

भाजपा ने घोषणापत्र में आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी घोषणाएँ प्रस्तुत की हैं। इनमें गरीब परिवारों को हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, प्रत्येक घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पेयजल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,00,00 रुपये प्रति माह करना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के जरिए पार्टी ने सीधे तौर पर आम मतदाताओं को साधने की कोशिश की है।

## भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया

विवी राजेश सहित, अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे।

भाजपा ने घोषणापत्र में आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी घोषणाएँ प्रस्तुत की हैं। इनमें गरीब परिवारों को हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, प्रत्येक घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पेयजल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,00,00 रुपये प्रति माह करना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के जरिए पार्टी ने सीधे तौर पर आम मतदाताओं को साधने की कोशिश की है।